harness the best of production, processing, and management technologies for achieving self reliance quickly.

The improvements in per capita consumption has also to come about through higher per capita incomes, which is one of the main objectives of planned development and the programmes for employment generation and poverty alleviation.

Revival of sugar factories in Assam

833. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have constituted a six-member high level team for revival of existing sugar factories and improving sugarcane cultivation in Assam; and

(b) if so, by when the findings of the high level team are likely to be received?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir. However, subsequently, two more members have been added to this Team.

(b) The Study Team has been asked to submit its report within 3 months.

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

834. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों, विशेषकर दालों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) मूल्यों को जून, 1991 में विद्यमान मूल्यों के स्तर पर वापस लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खाद्यान्नों के थोक मूल्य सूचकांक में मार्च, 1991 की तुलना में 9 नवम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1990 में उसी अवधि के दौरान सूचकांक में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । जहां तक दालों का संबंध है, थोक मूल्य सूचकांक में मार्च, 1991 की तुलना में 9 नवम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि 1990 में उसी अवधि के दौरान सूचकांक में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) खाद्यान्नों और दालों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(1) कमी के मौसम में मांग को पूरा करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये केन्द्रीय पूल से चावल के आवंटन को जुलाई, 1991 से पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है।

(2) केन्द्रीय पूल से पंजाब और हरियाणा के लिये गेहूं के आवंटनों को अक्तूबर, 1991 से बढ़ा दिया गया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके तथा बाजार पर बने दबाव को कम किया जा सके ।

(3) भारतीय खाद्य निगम को सितम्बर-अक्तूबर, 1991 के दौरान खुले बाजार में 3 लाख मीटरी टन चावल और 3 लाख मीटरी टन गेहूं बेचने के लिये प्राधिकृत किया गया था। दिसम्बर, 1991 में 3 लाख मीटरी टन और गेहूं बेचने के लिये भी उन्हें प्राधिकृत किया गया है ।

(4) दालों की पैदावार से अधिक मांग को पूरा करने के लिये दालों की पैदावार को बढ़ाने के लिये कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं । खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी०एल०) पर आयात के जरिये भी दालों की उपलब्धता में वृद्धि की जा रही है ।